

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1936 (शठ)

(संO पटना 652) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2014

सं0 I/एम¹-1-54/2014—**3361**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

संकल्प

7 अगस्त 2014

बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली 2014 के द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली 1995 यथा संशोधित के नियम—8(1) में संशोधन कर राज्य के जिलों में अधिसूचित भूमि/सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी को पुनरीक्षित करने हेतु राज्य सरकार की अनुमित का प्रावधान किया गया है एवं नियम—6(2)(च)(ix) द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि पुनरीक्षण के दौरान जिला मूल्यांकन समिति पूर्व के मूल्यांकन में प्रचलित बाजार मूल्य से ज्यादा दर पाए जाने पर उक्त दरों को प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य अनुशंसित कर सकेगी।

- 2. राज्य सरकार को यह समाधान हुआ है कि वर्ष 2012—13 के पुनरीक्षण में नियम—6(2)(छ) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपित प्राप्त करने के क्रम में व्यापक प्रचार प्रसार में कमी रहने कारण आपित्तयाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हुई, साथ ही प्राप्त आपित्तयों का निस्तार तार्किक ढ़ंग से नहीं किया जा सका। जिससे वर्ष 2012—13 की तुलना में वर्ष 2013—14 में लगभग सभी जिलों के अनेक राजस्व ग्रामों के MVR में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है।
- 3. अतएव राज्य सरकार बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली 2014 के नियम–8(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी समाहर्त्ता—सह—अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति को

नियम—6(2)(च)(ix) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त कंडिका—02 में वर्णित विसंगति का निराकरण सुनिश्चित कराने हेतु पुनरीक्षण की अनुमित देती है। यह अनुमित मात्र MVR की दरों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य करने हेतु दी जाती है।

- 4. सभी समाहर्ता—सह—अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन सिमति विशेष विज्ञापन निकालकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से 45 दिनों के अंदर वर्त्तमान न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी पर आपित प्राप्त कर तथा आपित्तयों का सत्यापन एवं निराकरण कर जिला मूल्यांकन सिमति की अनुशंसा के पश्चात् पुनरीक्षित MVR अधिसूचित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5. राज्य मूल्यांकन समिति इस हेतु जिला मूल्यांकन समिति को उक्त नियमावली के नियम—6(1) के तहत उचित निर्देश देकर इसे फलित कराएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 652-571+500-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in